

अवैध कटाई में संलिप्त वन माफियाओं को पकड़ने की मुहिम जारी

भोपाल। वन विभाग द्वारा सामान्य की अवैध कटाई करने वाले वन माफियाओं को गिरफतार करने की मुहिम चलायी जा रही है। इसी क्रम में वन मण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल, सामान्य वन मण्डल के परिक्षेत्र बैतूल सामान्य वन मण्डल में 18 एवं 19 नवम्बर को वन विभाग द्वारा राजि गश्त के द्वारां खारी बीट में जाँच करने पर सामान की लकड़ी से भरा अशाक लालोंग पिसी ट्रक जस कर वन अपराध पंजीबद्ध किया गया। वाहन की जाँच करने पर वाहन में रामकृष्ण बल्द पुरुषोंपर मेहरा के नाम के द्वायविंग लायरेसें की छायांगति प्राप्त हुई। इसके आधार पर वन मण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल श्री नवनीन गर्ग सामान्य वन मण्डल के निर्देशन में उप वन मण्डलाधिकारी श्री श्रेयस श्रीवास्तव और परिक्षेत्र अधिकारी श्री ए.एस. बघेल के नेतृत्व में अलग-अलग दल गठित कर विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गयी। छापामार कार्रवाई में वाहन का रामकृष्ण मेहरा निवासी राहुल नगर मण्डीप्रेषण लायरेसें को गिरफतार कर बयान दर्ज किये गये। आरोपी रामकृष्ण मेहरा ने बयान में यह बताया कि उसके द्वारा राजू वाडीवा निवासी ग्राम पार्वती तहसील शाहपुर के साथ में सामान कटाई कर परिवहन किया गया। वन विभाग द्वारा पूर्व में 27 अक्टूबर को 3 आरोपियों में राजा राजू वाडीवा, शेख अफजल और पाढ़ के सोनू मुहुर्दीन की गिरफतारी की जा चुकी है। वन विभाग की टीम द्वारा 22 नवम्बर को आरोपी को न्यायालय द्वारा उसके बयान के आधार पर पूछताल पर भेजा गया है। आरोपी रामकृष्ण मेहरा को 25 नवम्बर को मैटिकल परीक्षण के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की विवेचना में आरोपी द्वारा किये गये अपराध के आधार पर 7 दिसंबर 2024 तक ज्यूरीशियल रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में आगामी कार्रवाई की जा रही है।

दिव्यांग प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने सरकार प्रतिबद्ध - मंत्री श्री कुशवाह

भोपाल। सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं उत्तानिके मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने मंगलवार को ज्ञालियर में इंटर स्टेट वुमन ब्लाइंड किंटेर टूनमेंट का उद्घाटन किया। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन शावल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांग प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। सरकार द्वारा दिव्यांग खिलाड़ियों को हर संभव खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मंत्री श्री कुशवाह ने दूनमेंट में भाग ले रही किंटेर टीम के सदस्यों से परिचय प्राप्त कर उन्हें प्रोत्साहित किया। ज्ञालियर के एलपीएसीपी फॉर्म द्वालाइंड मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित प्रतियोगिता 03 दिसंबर तक चलेगी। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश की टीमें हिस्से ले रही हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर अध्यक्ष किंटेर एसोसिएशन फॉर्म द्वालाइंड के अध्यक्ष डॉ. रामेंद्र शमा, श्री अतुल अत्तराली, श्री एस.के. अग्रवाल सहित अंतिथियों ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया एवं मैच का आनंद लिया।

प्रदेश में दिव्यांग छात्रावास की स्थापना एवं संचालन

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों पर दिव्यांग विवार्थियों के लिये 50 सीटर बालक और 50 सीटर बालिका दिव्यांग छात्रावास के निर्माण के लिये 3 करोड़ 46 लाख रुपये प्रति इकाई के मान से स्वीकृति प्रदान की गयी है। छात्रावास का निर्माण संभागीय मुख्यालयों पर स्थित ऐसे स्कूलों में किया जायेगा, जहां सह-शिक्षा उपलब्ध है। वर्तमान में ऐसे दिव्यांग विवार्थी, जो कक्षा-8वीं तक की शिक्षा राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित छात्रावास में हक्कर करते हैं, उत्तरी होने पर लिये उच्चतर माध्यमिक जिक्षाओं में पढ़ाई के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित छात्रावासों में व्यवस्था की गयी है। स्वीकृत छात्रावासों में से ज्ञालियर, जबलपुर तथा शहडोल में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष स्थानों पर छात्रावास भवनों का निर्माण प्रगति पर है।

प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक शहडोल श्री पटेल निलंबित

भोपाल। राज्य शासन द्वारा प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रण शहडोल श्री विरपिन पटेल को निलंबित कर दिया गया है। श्री पटेल को समर्थन मूल्य पर शिवपुरी जिले की सेवा सहकारी विभागों और नारायण समाज के विच समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ऐसा पारिसंरक्षितीकी तंत्र बनाने के लिये प्रतिबद्ध है, जहां महिलाएं हिंसा और भेदभाव के बिना आगे बढ़ सके।

कार्यशाला के स्कार्ड सेशन की संस्थापक सृष्टि प्रगत ने युवा पीढ़ी की बदलाव लाने की आपास क्षमता को उत्ताप किया और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से मुक्त एक भविष्य बनाने में उनके योगदान की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने सामूहिक प्रयासों और सक्रिय युवा भागीदारी को बढ़ाया, जिससे प्रगतीलाभ समस्याओं का समाधान किया जा सके, और यह सुनिश्चित किया जा सके।

रेडियो बुद्धेलखण्ड की ओर, जे. सुनी वर्मा ने कैसे युवा सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक बन सकते हैं पर चर्चा की। इसमें यूनिसेफ के अधिकारियों के साथ-साथ अंतर्भूत और उदय के युवाओं ने अपनी परिवर्तनकारी जीवनियाँ और लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जामीन स्तर पर संर्घण्य की रणनीतियाँ साझा कीं। इस

मध्यप्रदेश वरिष्ठ नागरिक नीति को और ज्यादा प्रासंगिक बनाने पर जोर

भोपाल। मध्यप्रदेश वरिष्ठ नागरिक नीति का मुरीरीक्षण कर इसे वर्तमान परिप्रेक्षण में अधिक प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। विशेषज्ञ एवं नीति निधिरक्षकों ने यह विचार मंगलवार को होटल पलास भोपाल में बुद्धजन कल्याण के लिए आयोजित कार्यशाला में व्यक्त किये। मध्यप्रदेश योजना आयोग और सामाजिक न्याय एवं परिवार्यांगन कल्याण संस्कृतिकरण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मध्यप्रदेश में बुद्धावस्था के लिए एक आधानिक दृष्टिकोण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया हुआ। राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और नीति निर्माताओं के आयोजनालय में भाग लिया।

मध्यप्रदेश में यह बुद्धजन आयोजित रैमांड पर भेजा गया है। 2021 की जनगणना के अनुसार, राज्य में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 57.13 लाख थी, जो 2031 तक बढ़कर 11.19 लाख ने का अनुमान है। समाज में बदलते पारिवारिक ढाँचे, स्वास्थ्य समस्याओं, डिजिटल ग्रैड्योगिकी तक सीमित पहुंच और वित्तीय

भोपाल

भोपाल। मध्यप्रदेश वरिष्ठ नागरिक नीति का बुद्धजन आयोजित कार्यशाला का आयोजन किया गया। वाहन की जाँच करने पर वाहन में रामकृष्ण बल्द पुरुषोंपर मेहरा के नाम के द्वायविंग लायरेसें की छायांगति प्राप्त हुई। इसके आधार पर वन मण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल श्री नवनीन गर्ग सामान्य वन मण्डल के निर्देशन में उप वन मण्डलाधिकारी श्री ए.एस. बघेल के नेतृत्व में अलग-अलग दल गठित कर विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गयी। छापामार कार्रवाई में वाहन का रामकृष्ण मेहरा निवासी राहुल नगर मण्डीप्रेषण को गिरफतार कर बयान दर्ज किये गये। आरोपी रामकृष्ण मेहरा को बयान में यह बताया कि उसके द्वारा राजू वाडीवा निवासी ग्राम पार्वती तहसील शाहपुर के साथ में सामान कटाई कर परिवहन किया गया। वन विभाग द्वारा पूर्व में 27 अक्टूबर को 3 आरोपियों में राजा राजू वाडीवा, शेख अफजल और पाढ़ के सोनू मुहुर्दीन की गिरफतारी की जा चुकी है। वन विभाग की टीम द्वारा 22 नवम्बर को आरोपी को न्यायालय द्वारा उसके बयान के आधार पर पूछताल पर भेजा गया है। आरोपी रामकृष्ण मेहरा को 25 नवम्बर को मैटिकल परीक्षण के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की विवेचना में आरोपी द्वारा किये गये अपराध के आधार पर 7 दिसंबर 2024 तक ज्यूरीशियल रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में आगामी कार्रवाई की जा रही है।

उपर्युक्त विवरण के लिये 3 दिवस की लिये रामकृष्ण प्रेषण के बाद न्यायालय में आयोजित प्रस्तुति किया गया। वन विभाग द्वारा पूर्व में 27 अक्टूबर को 3 आरोपियों में राजा राजू वाडीवा, शेख अफजल और पाढ़ के सोनू मुहुर्दीन की गिरफतारी की जा चुकी है। वन विभाग की टीम द्वारा 22 नवम्बर को आरोपी को न्यायालय द्वारा उसके बयान के आधार पर पूछताल पर भेजा गया है। आरोपी रामकृष्ण मेहरा को 25 नवम्बर को मैटिकल परीक्षण के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की विवेचना में आरोपी द्वारा किये गये अपराध के आधार पर 7 दिसंबर 2024 तक ज्यूरीशियल रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में आगामी कार्रवाई की जा रही है।

उपर्युक्त विवरण के लिये 3 दिवस की लिये रामकृष्ण प्रेषण के बाद न्यायालय में आयोजित प्रस्तुति किया गया। वन विभाग द्वारा पूर्व में 27 अक्टूबर को 3 आरोपियों में राजा राजू वाडीवा, शेख अफजल और पाढ़ के सोनू मुहुर्दीन की गिरफतारी की जा चुकी है। वन विभाग की टीम द्वारा 22 नवम्बर को आरोपी को न्यायालय द्वारा उसके बयान के आधार पर पूछताल पर भेजा गया है। आरोपी रामकृष्ण मेहरा को 25 नवम्बर को मैटिकल परीक्षण के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वन विभाग द्वारा पूर्व में 27 अक्टूबर को 3 आरोपियों में राजा राजू वाडीवा, शेख अफजल और पाढ़ के सोनू मुहुर्दीन की गिरफतारी की जा चुकी ह

विचार

आदिवासियों-महिलाओं ने लगायी नैया पार

झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से सबसे ज्यादा जैएमएम ने कुल 34 सीटें जीती। वहीं, कांग्रेस ने 16, राजद ने 4 और सीपीआई (एमएलएल) ने 2 सीटें जीती। यानी कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन ने राज्य की कुल 81 में से 56 सीटें प्राप्त कर अपनी सरकार बचा ली है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन से भाजपा ने 21, आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास ने एक-एक सीटें जीतीं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ नए और पुराने नेताओं को लेकर लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किसे नेतृत्व सौंपा जाए नए, तेज-तरार और यवा नेता को अथवा पुराने, स्थापित और मंझे हुए नेता को। ऐसा बताया जाता है कि पार्टी के भीतर मतभेद-मनभेद रहने के कारण इस बात पर एक राय नहीं बन पाई कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले उसकी ओर से किस नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। यही कारण है कि बड़ी संख्या में राज्य की गैर-आदिवासी जनता ने भी साथ नहीं दिया, जबकि भाजपा ने राज्य में चुनाव प्रचार में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से लेकर तमाम स्टार प्रचारकों ने कमान संभाल रखी थी। यहां तक कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा राज्य में दो महीने तक जमे रहे, जिन्होंने बांग्लादेश से 'घुसपैठियों' को आने देने के लिए सोरेन सरकार पर ज़ोरदार हमले किए। गौरतलब है कि भाजपा ने अपनी रैलियों में झारखंड की 'माटी, बेटी और रोटी' का मुद्दा उठाया। इस मामले में भाजपा के नेताओं ने हमंत सोरेन की सरकार पर आरोप लगाए कि राज्य में 'माटी, बेटी और रोटी' खतरे में हैं। इन सबके बीच झारखंड में भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा के भीतर ऐसे प्रभावशाली चेहरे का अभाव रहा, जो जनता को प्रभावित कर अपनी ओर आकर्षित कर सके। जिस प्रकार उश्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी को विजयी बनाने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है और चुनाव-दर-चुनाव सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पार्टी के लिए एक जिम्मेदार चेहरा हैं, वैसे ही चुनाव से पहले झारखंड में भी पार्टी को एक जिम्मेदार चेहरा नहीं मिला। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से पहले ही दिन से यह बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि यदि इंडिया गठबंधन ने चुनाव जीता तो उनकी ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा हमंत सोरेन ही होंगे। हालांकि, भाजपा के भीतर कई नेता हैं जो हमंत सोरेन को कड़ी टक्कर देने में सक्षम हैं। यहां तक कि कुछ नेता तो उनसे बेहतर परफॉरमेंस करने की क्षमता और कौशल भी रखते हैं, लेकिन पार्टी की ओर से उन्हें आगे नहीं करने के कारण मतदाताओं के बीच इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।

कनाडा एवं अमेरिका से भारत में रिवर्स ब्रेन इंजन की सम्भावना बढ़ रही है

हैं। हालांकि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की संख्या लगभग नगण्य सी ही है परंतु ट्रम्प प्रशासन द्वारा अब बीजा, एच1बी सहित, जारी करने वाले नियमों को और अधिक कठोर बनाया जा सकता है। अमेरिका में प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले कुल एच1बी बीजा में से 60 प्रतिशत से अधिक बीजा भारतीय मूल के नागरिकों को जारी किए जाते हैं। यदि इस संख्या में भारी कमी दृष्टिगोचर होती है तो अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को, उनकी पढ़ाई सम्पन्न करने के पश्चात यदि एच1बी बीजा जारी नहीं होता है तो उन्हें भारत वापिस आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार अमेरिका से भी भारतीयों का रिवर्स ब्रेन ड्रेन दिखाई पड़ सकता है। भारत आज पूरे विश्व में सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है, अतः भारत में तेज गति से हो रहे आर्थिक विकास के कारण सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, उच्च तकनीकी क्षेत्रों, वाहन विनिर्माण उद्योग, फार्मा उद्योग, चिप विनिर्माण उद्योग, स्टार्ट अप, आदि क्षेत्रों में भारी मात्रा में रोजगार के नए अवसर निर्मित हो रहे हैं और भारत को इन क्षेत्रों में उच्च टेलेंट की आवश्यकता भी है। यदि कनाडा एवं अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त एवं उक्त क्षेत्रों में प्रशिक्षित इंजीनीयर्स भारत को प्राप्त होते हैं तो यह स्थिति भारत के लिए बहुत फायदेमंद होने जा रही है।

भारत की ओर रिवर्स ब्रेन ड्रेन इसलिए भी होता दिखाई दे रहा है क्योंकि, भारत में आज मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किसी भी दृष्टि से भारत का आधारभूत ढांचा आज किसी भी विकसित देश की तुलना में कम नहीं है। साथ ही,

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

इमरजेंसी लाइट की तरह रोशनी दिखाता संविधान

उमेश चतुर्वेदी

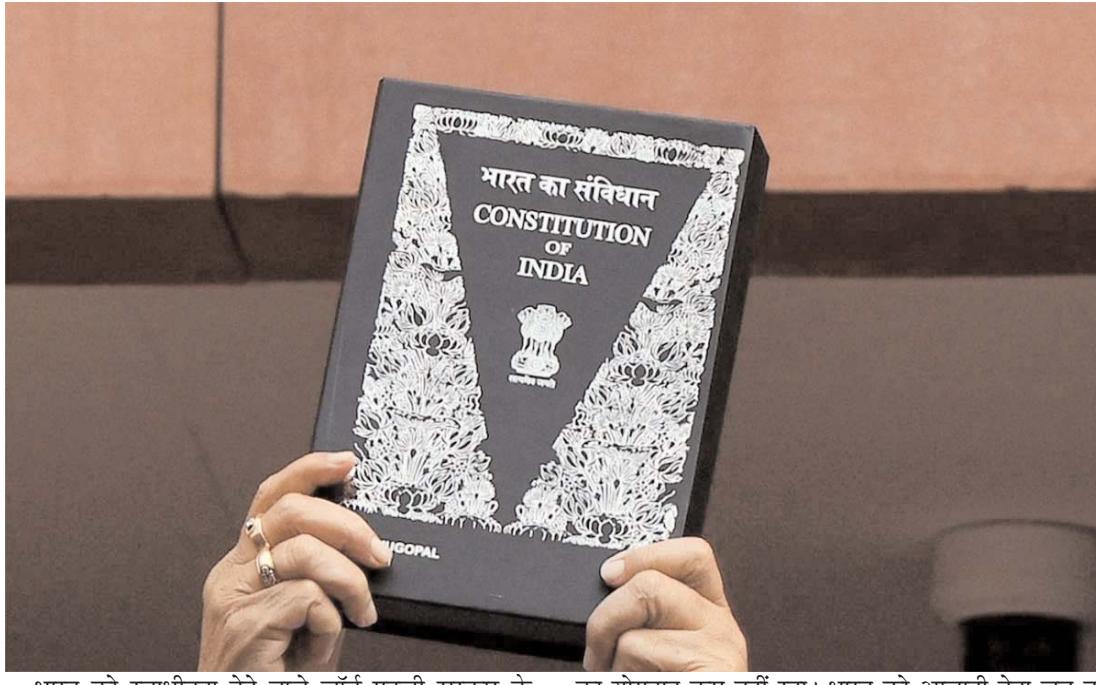
भारतीय संविधान इमरजेंसी लाइट की तरह है।

**जब कभी हालात का बना अधरा देश के सामने
उलझन जैसी स्थिति पैदा करते हैं, संविधान खुद-
बनावट उचला बन सामने हाजिर हो जाता है।**

**ब-छुड़ उत्ताला बग सानग हाईर हो जाता है।
संविधान के अंजोर में देश को सही राह दिख जाती है। आपातकाल जैसे एक-आध अपवादों को छोड़**

दें तो पचहार साल से यह संविधान हमारे लिए रोशनी की लकीर बना हुआ है। देश के सामने जब ये अपनी भवित्वता लौटे तो उसे भौतिक से भी

**भा भटकाव जस हालात हात ह, सावधान स हा
आओ तदने की ग़ह निकल आती है।**



भारत के स्वाधीनता दिन बाल लाड एटला सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ब्रिटिश संसद में पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन विपक्षी नेता विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि आजाद होते ही भारत बिखर जाएगा और वहां दुर्दृश्य, बदमाशों और लुटेरों के हाथ चला जाएगा। लेकिन चर्चिल की इस चाहत को स्वाधीन भारत की मनीषा और लोकतंत्र ने ध्वस्त कर दिया। दुनिया के विकसित और बड़े माने जाने वाले लोकतंत्रों में भी संवैधानिक व्यवस्था लागू होने या स्वाधीनता के तुरंत बाद समानता के आधार पर वयस्क मतदान का अधिकार नहीं मिला। लेकिन महज 18.33 प्रतिशत साक्षरता वाला देश लोकतंत्र की मजबूत राह पर चल पड़ा। ये सब उपलब्धियां अगर भारतीय लोकतंत्र को हासिल हुई हैं, तो इसकी मजबूत बुनियाद भारतीय संविधान ने रखी। लोकतांत्रिक शासन की बुनियाद पर भारत राष्ट्र की जो मजबूत इमारत खड़ी हुई है, वह मजबूत संवैधानिक बुनियाद के बिना संभव नहीं हो सकता था।

इसी भारतीय संविधान ने 26 नवंबर के दिन 75 साल की यात्रा पूरी कर ली है। 64 लाख रुपए के कुल खर्च और दो साल 11 महीने 18 दिन तक चली बहसों के बाद इसी दिन 1949 में देश ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। इसके ठीक दो महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को देश ने इसे लागू किया और तब से यह हमारी लोकतांत्रिक राष्ट्र यात्रा की आत्मा, धड़कन, रक्त बना हुआ है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को हमने संविधान के विरासत के रूप में उन्हींका कर्म दिया है, लेकिन संविधान के

का योगदान कम नहीं रहा। भारत का आजादा दिना जब तथा हुआ, उसके पहले पंडित नेहरू की अगुआई में एक अंतर्रिम सरकार बनी। उसी अंतर्रिम सरकार के मुखिया के नाते जवाहरलाल नेहरू और उप-प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने कर्णाटक के जाने माने विधिवेत्ता बेनेगल नरसिंह राव यानी बीएन राव को विधि सलाहकार के पद पर नियुक्त करके संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी थी मद्रास और कैर्किंबिज विश्वविद्यालय से पढ़े राव 1910 में भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए। साल 1939 में राव को कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 1944 में उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया। भारत सरकार के संविधान सलाहकार के नाते उन्होंने वर्ष 1945 से 1946 तक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि की यात्रा की और तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने 395 अनुच्छेद वाले संविधान का पहला प्रारूप तैयार करके संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा. आंबेडकर को सौंप दिया।

29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की बैठक में कहा गया कि संविधान सलाहकार बीएन राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार कर उसे संविधान सभा में पारित करने हेतु प्रेषित किया जाए। संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करते हुए 26 नवंबर 1949 को भीमराव आंबेडकर ने जै भाषण दिया था, उसमें उन्होंने संविधान निर्माण का श्रेय बीएन राव को भी दिया है। भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ ही राज्यों

और संघ के बीच शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत और नीति निर्देशक तत्व इन विशेषताओं में प्रमुख माने जाते हैं। मूल अधिकारों की व्यवस्था के साथ ही कानून के सामने सभी नागरिकों के बराबर होने की बात भारतीय संविधान की ताकत है। भारतीय संविधान कठोर भी है तो लचीला भी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक संविधान में 127 संशोधन हो चुके हैं। कुछ जानकार इसे संविधान की कमज़ोरी बताते हैं तो कई के अनुसार यह संविधान की ताकत है। इन संशोधनों के बहाने तर्क दिया जाता है कि अपना संविधान जड़ नहीं है।

चाहे अच्छाई का संदर्भ हो या कमज़ोरी का, पूरी तरह अच्छा या बुरा होने का विचार हकीकत नहीं हो सकता। तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र और अध्यात्म, तीनों की मान्यता है कि पूर्णता का प्रतीक सिर्फ ईश्वर होता है, विचार या व्यक्ति नहीं। कुछ इसी अंदाज में भारतीय संविधान भी कुछ भारतीय विषयों को सही तरीके से चूक गया है। संविधान सभा की आखिरी बैठक के दिन संविधानसभा के सदस्य महावीर त्यागी ने सवाल पूछा था, 'अपने संविधान में कहाँ हैं गांधी जी, कहाँ हैं गांधी के विचार।' बेशक तब तक गांधी की हत्या हो चुकी थी, लेकिन गांधी के विचारों की तासीर तब तक आज की तुलना में कहीं ज्यादा महसूस की जा रही थी। भारतीय आजादी हर भारतीय के संघर्ष का नतीजा है, लेकिन गांधी की अगुआई, उनकी वैचारिक रोशनी और रचनात्मक कार्यों के बिना आजादी की कल्पना भी बेमानी है। दिलचस्प यह है कि संविधान में महावीर त्यागी को गांधी के इन रूपों के दर्शन नहीं हो पाए। दरअसल गांधी भारतीय संविधान में देश की मूल इकाई गांव को बनाना चाहते थे, व्यक्ति को नहीं। भारतीय परंपरा में व्यक्ति की महत्ता तो है, लेकिन वह सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति की सामाजिकता का बेहतर रूप ग्रामीण समाज है। लेकिन गांधी के इस विचार को नेहरू ने ही नहीं, अंबेडकर ने भी नकार दिया। नकारने को लेकर दोनों के शब्द बेशक अलग थे, लेकिन उनका बोध एक ही था। दोनों का मानना था कि सदियों से बजबजा रहे गांव भारतीय लोकतंत्र को राह नहीं दिखा सकते।

संविधान सभा में कई मुद्दों पर सदस्यों के बीच तीखा बहसें हुईं। आज जिसे हम लोकशाही या नौकरशाही कहते हैं, उसके अधिकारों को लेकर भी तीखी बहस हुई। दिलचस्प यह है कि संविधान सभा के कई सदस्यों को ब्यूरोक्रेसी को संवैधानिक अधिकार संपन्न बनाने पर एतराज था। उनका मानना था कि वे जैसा ही काम करेगी, जैसा अंग्रेजी सरकार के दौरान करती थी। एम ए अयंगार जैसे वरिष्ठ और माननीय सवाल ने नौकरशाही को वेतन और अधिकार की गारंटी देने पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि जब आम आदमी को रोटी और कपड़ा की गारंटी नहीं है, तो उन अधिकारियों को गारंटी क्यों दी जाए, जो विदेशी सत्ता की कठपुतली थी। तब पटेल ने अधिकारियों को ताकत देने का बचाव करते हुए तर्क दिया था कि एक बार अफसरशाही स्थापित हो जाएगी तो अधिकारी बदलाव के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अधिकारी बदलाव को राजी हुए, क्या वे लोकोन्मुख हुए, क्या उनका व्यवहार पुराने जर्मांदारों, रजवाड़ों या अंग्रेजों जैसा नहीं है? अपवादों को छोड़ दें तो कितने अधिकारी ऐसे हैं, जो खुद को आम लोगों जैसा मानते हैं और विशेषाधिकार नहीं चाहते?

भारत की भाषा समस्या का समुचित समाधान संविधान में नहीं दिखता। देसी होकर भी हिंदी अब भी दक्षिण और पूर्व के कुछ राज्यों के लिए स्वीकार्य नहीं बन पाई है और विदेशी अंग्रेजी इस देश की असल ताकतवर और राजभाषा बनी हुई है। हिंदी की जगह भारतीय भाषाओं की बात करने से हिंदी विरोध की आंच धीमी तो हो जाती है, लेकिन अंग्रेजी की ताकत नहीं घटती। अंबेडकर चाहते थे कि संस्कृत राजभाषा हो, लेकिन नेहरू के दबदबे के चलते अपनी राय को मजबूती से रख नहीं पाए।

के चलते गाव हमार विकास प्राकृत्या और शासन का इकाई होते। तब आज का भारतीय परिदृश्य बदला हुआ होता। भारतीयता की संौधी गमक के साथ अंदरूनी पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याएं कावू में रहतीं। अधिसंच्छ जनसंख्या गांवों में ही रहती। शहरीकरण तेज नहीं होता और जनसंचिक्यी दबाव से शहरी ढांचा चरमरा नहीं रहा होता। इसी तरह अगर अफसरशाही को संवैधानिक गरांटी नहीं मिली होती तो बराबरी का भाव कहीं ज्यादा होता, तब अफसरशाही माने भ्रष्टाचार नहीं होता, तब हर रोग की जड़ी और इलाज अफसरशाही को ही नहीं माना जाता।



भारत में, विकसित देशों की तुलना में, मुद्रा स्फीति की दर कम होने से, सामान्य रहन सहन की लागत तुलनात्मक रूप से भारत में बहुत कम है। अतः भारत में अमेरिका एवं कनाडा की तुलना में शुद्ध बचत दर भी अधिक है। हाल ही के समय में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। आज बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में बहुत ही कम लागत पर अमेरिकी अस्पतालों की तुलना में (अमेरिका की तुलना में तो 1/10 लागत पर) अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में तो शुद्ध हवा एवं शुद्ध पानी, जो स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने में सहायक होता है, पर्याप्त

मात्रा में उपलब्ध है। वरना, महानगरीय इलाकों में तो आज सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। विभिन्न देशों से उच्च शिक्षा प्राप्त एवं टेलेंटेड भारतीय जो भारत वापिस लौटे हैं, उन्होंने अपने नए प्रारम्भ किए गए स्टार्ट अप के कार्यालय दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए हैं।

भारत में बहुत लम्बे समय से मजबूत लोकतंत्र बना हुआ है एवं केंद्र में एक मजबूत सरकार, उद्योग एवं व्यापार को भारत में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग एवं व्यापार के मित्रवत आर्थिक नीतियों को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा में अपार वृद्धि दृष्टिगोचर हु

है। विकसित देशों में नागरिकों की औसत आयु 50 वर्ष से अधिक हो रही है जिससे श्रमिकों की संख्या इन देशों में लगातार कम हो रही है एवं श्रम लागत में भी भारी मात्रा में वृद्धि हुई है जिसके कारण इन देशों में उत्पादन लागत बहुत अधिक बढ़ गई है। हाल ही के समय में चीन भी इस समस्या से ग्रसित पाया जा रहा है। केवल भारत एवं दक्षिणी अफ्रीकी देशों में ही श्रम लागत तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। इसके कारण विश्व की कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी विनिर्माण इकाईयों की स्थापना भारत में करना चाहते हैं। भारत में उत्पादों का निर्माण कर इन उत्पादों को विश्व के अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है।

भारत में आटोमोबाईल उद्योग, मोबाइल उद्योग एवं फार्मा उद्योग इसके जीते जागते प्रमाण हैं। इन्हीं कारणों से आज भारत से कई उत्पादों का निर्यात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है एवं भारत का विदेशी व्यापार घाटा लगातार कम हो रहा है। विदेशी व्यापार घाटे में सुधार होने के चलते भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में भी बृद्धि दृष्टिगोचर है जो हाल ही के समय में 70,000 अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को भी पार कर गया था। हालांकि, इसके बाद से इसमें कुछ गिरावट देखी गई है। आज विश्व के कई विकसित देशों में सामाजिक तानाबाना छिन्न भिन्न हो गया है एवं इन देशों के नागरिकों में मानसिक असंतोष की भावना लगातार बढ़ रही है एवं इन देशों की आधे से अधिक आबादी आज मानसिक बीमारियों से ग्रसित है। जबकि इसके ठीक विपरीत भारत में हिंदू सनातन संस्कृति के संस्कारों के अनुपालन से एवं संयुक्त परिवार की जीवनशैली के चलते भारतीय नागरिक मानसिक बीमारियों से लगभग पूर्णतः मुक्त रहे हैं एवं सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

मुर्मु चार दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु पहुंची

चेन्नई(एजेंसी)। राष्ट्रपति द्वारा पूर्व बुधवार को चार दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु पहुंची। श्रीमती मुर्मु विशेष विमान से कोंबंडूर में सुलूर हवाईअड़े पर उतरी, जहां उनका गर्मजोरी से स्वागत किया गया। इसके बाद वह पहाड़ी जिले नीलगिरी के उदगामेंडलम में राजभवन में रात्रि विश्राम के लिए रहाना हो गयी। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने वहां उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति 28 नवंबर को रक्षा सेवा स्प्रिंफ कॉलेज, वेलिंगटन के सकाय एवं छात्र अधिकारियों को संबोधित करेगी। वह 29 नवंबर को आदिवासी महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की सरकारी एवं आदिवासी समुदाय के प्रमुख सदस्यों से नीलगिरी जिले के उदगामेंडलम स्थित राजभवन में बातचीत करेगी। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्रीमती मुर्मु 30 नवंबर को तिरुवरम में तमिलनाडु के केन्द्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेगी। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं, मोदी-शाह का हर फैसला मंजूर: शिंदे

मुंबई(एजेंसी)। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर संसदें के बीच कार्रवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने आज थाएं में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इतनी बड़ी जनादेश के लिए महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लोगों ने महायुद्धी को विकास के काम के लिए अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि जो काम महा विकास आधारी ने रोक दिया था, उसे हमने फिर से शुरू किया और इसी वजह से जनता का समर्थन हमें हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने भी जबरदस्त मेहनत की। उन्होंने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं, बल्कि एक कॉमन मैन बनकर काम किया। आम लोगों को जहां-जहां प्रॉलेट महाराष्ट्र होती है, उसको हमने समझने के बाद काम किया। शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि मैं कभी अपने आप को सीएम नहीं समझा। हमने आप आदमी बनकर काम किया। यही कारण है कि हमने तमाम बड़ी योजनाओं पर काम किया। हम लाइकी बहन योजना लेकर आए। हमने परिवार के हर सदस्य को सरकार की ओर से कुछ ना कुछ देने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पूरा समर्थन था। दोनों ने हमें जनता के लिए काम करने को कहा था और हमने किया।

डंपर पुलिया नें पलटा, एक की मौत, एक गंभीर

सीहोर(एजेंसी)। मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के आषां में आज डंपर ओरियरेक करने के प्रयास में पुलिया में पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी और एक गंभीर हुआ है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक डंपर ओरियरेक के प्रयास में पलट गया। इस हादसे में बाइक सवार और पिकअप चालक डंपर के नीचे ढाके गए। पुलिस द्वारा जेसीबी, पोकलेन और झेन की सहायता से दो घंटे से अधिक समय तक चले रेस्क्यू आपरेशन के बाद एक युवक का शव मलवे से निकला है। जबकि एक अन्य डंपर चालक भी घायल हो गया।

अडानी मुद्दे पर संसद में व्यापक चर्चा जरूरी: कांग्रेस

नवी दिल्ली(एजेंसी)। कांग्रेस ने कहा है कि अडानी समूह पर दुनिया के कई देशों में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका बचाव करने की बजाए उन्हें पिरफ्टार कर इस मुद्दे पर संसद में व्यापक चर्चा करानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता मुस्तिरा श्रीनेत ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह गंभीर मामला है और इस पर संसद में नियम 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए। सदन मोदी वंदन के लिए नहीं है। लाखों करोड़ों की हेरोफेरी और धूस देने वाले अडानी के गिरफ्तार कर सदन में उन पर लगे आरोपों को लेकर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। सेबी जैसे संस्थान इन आरोपों की निष्पक्ष



जांच करें और श्री मोदी, उनकी सरकार के मंत्री, भाजपा और उसके सांसद अडानी का बचाव करना छोड़ दें। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता गहुल गंधी ने संसद भवन में प्रतकर्ताओं के सवालों के जवाब में कहा है कि उद्योगपति अडानी को गिरफ्तार किया जाए।

जाना चाहिए, लेकिन उन्हें बचाया जा रहा है। सैकड़ों लोगों को मामूली आरोपों के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है लेकिन सरकार उनको बचा रही है। श्रीमती श्रीनेत ने कहा कि अडानी सरकार एक ही उद्योगपति के एकाधिकार को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत ही नहीं अमेरिका, स्वीटर्जरलैंड, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, इजराइल सहित दुनिया के कई देशों में अडानी समूह पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन भारत सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हर ओर से सिर्फ अडानी समूह के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत को बंगलादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत को बंगलादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत को बंगलादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत को बंगलादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत को बंगलादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत को बंगलादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत को बंगलादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत को बंगलादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत को बंगलादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत को बंगलादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत को बंगलादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत को बंगलादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत को बंगलादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत को बंगलादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत को बंगलादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन भारत को बंगलादेश

पहलवान साक्षी मलिक के घर आई नन्हीं मेहमान

नई दिल्ली (एजेंसी)। पहलवान साक्षी मलिक ने बेटी को जन्म दिया है, इसकी जारीरी उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से दी। पोस्ट में साक्षी मलिक ने बेटी के नाम का भी खुलासा किया। साक्षी ने अपने बेटी का नाम 3 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इंदिया के पूर्व अध्यक्ष बृहभूषण शरण पर कई चैपियंस विजेता साथीयोंशिदा पर खड़ा है। बता दें कि, साक्षी ने बेटी को जन्म 11 नवंबर को दिया था।

साक्षी ने अपने पोस्ट में लिखा कि, साक्षी और सत्यव्रत को ईश्वर के आशीर्वाद के पूर्ण धन की प्राप्ति हुई है। योशिदा ने 2002 बुसान एशियाई खेलों से 2016 रियो ओलंपिक तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 24 गोल्ड मेडल जीते। इसमें 3 ओलंपिक स्वर्ण मेडल भी से शेयर की गई। बेटी के

आरसीबी में शामिल होने के बाद विराट कोहली के बारे में ये क्या बोल गए फिल साल्ट?

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंग्लैंड के बल्लेबाज फिल साल्ट आईपीएल 2025 में आरसीबी का दिसंबर बनने को लेकर कफी उत्साहित हैं। बैंगलुरु ने उन्हें 11.50 करोड़ रुपये खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है। वहीं इस दौरान के बाद फिल साल्ट ने विराट कोहली के साथ खेलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि, आरसीबी से जुड़ने के बाद फिल साल्ट ने विराट कोहली के साथ खेलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बहुत सम्मान करता है। जब भी मैं उनके खिलाफ खेला, मुझे महेश हंसने और बात करने का मौका मिला। अब एक ही टीम में उनके साथ खेलने का मौका मिलना मेरे लिए खास है। इस धाकड़ बल्लेबाज ने आरसीबी

आईपीएल फाउंडर ललित मोदी ने किए बड़े खुलासे

नई दिल्ली (एजेंसी)। किया करते थे। उन्होंने कहा कि, उन्होंने अंपायरों को बदलने का काम भई किया वी है। उन्होंने आईपीएल फैंचाइजी के चेन्नई सुपर किंस के मालिक एन श्रीनिवासन पर फिक्सिंग के सर्गीन आरोप लगाए हैं। श्रीनिवासन भी साक्षीअई के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और उनके ललित मोदी के साथ मतभेद जग जाहिर हैं। अब एक पांडकास्ट पर चर्चा करते हुए ललित मोदी ने सोपासके के मालिक एन श्रीनिवासन पर आरोप लगाए हैं। इस वायरल पांडकास्ट पर ललित मोदी ने बताया कि, एन श्रीनिवासन चेन्नई सुपर किंस के मैचों में लेकिन उसके बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं।

